BRICS
INDIA 2021

ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्ष्यता में भारतीय सिविल सोसाइटी की मुख्य मांगें

नीति दस्तावेज़

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

BRICS
INDIA 2021

ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्ष्यता में भारतीय सिविल सोसाइटी की मुख्य मांगें

नीति दस्तावेज़

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

CONTENTS

परिचय	2
भारत के विकास में भारतीय सिविल सोसाइटी की भूमिका	3
कोविड -19 राहत कार्य	4
सिविल ब्रिक्स - विकास सहयोग में सिविल सोसाइटी से वार्तालाप के लिए एक मंच के रूप में	4
भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता एजेंडे को सिविल सोसाइटी की विकास मांगों से जोड़ना	5
बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार	5
सिविल सोसाइटी की मुख्य मांग: स्थानीय और वैश्विक स्तर पर नीतिगत निर्णयों में समावेशी भागीदारी	6
वैश्विक स्तर पर	6
एसडीजी की उपलब्धि के लिए डिजिटल और तकनीकी समाधानों का उपयोग करना	7
सामाजिक भलाई के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता से हानि	8
एसडीजी में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सिविल सोसायटी की मांग	9
पीपल टू पीपल एक्सचेंज को बढ़ाना	12
राष्ट्रीय विकास के लिए सुझाव	13

परिचय

एक बहुपक्षीय संगठन के रूप में ब्रिक्स ने आर्थिक और विकासात्मक सहयोग के लिए विभिन्न बहुपक्षीय प्रतिमानों में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह के रूप में जो अपने औसत सकल घरेलू उत्पाद के विषय में जी-7 देशों से आगे निकलने के लिए तैयार हैं, यह वैश्विक नीति निर्माण के रणनीतिक प्रपथ में काफी प्रभावशाली है। अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाने के लिए, जी-20 समूह में सहभागी समूहों के अनुभव को शामिल किया गया है और नीतिगत सामंजस्य और प्रभावशीलता के लिए स्वयं के उप-विषयक समूह बनाए गए हैं। ऐसा ही एक समूह जिसे हाल के वर्षों में रुझान प्राप्त हुआ है, वह है सिविल ब्रिक्स फोरम - सिविल सोसाइटी संगठनों[1] का एक गठबंधन जो ब्रिक्स देशों के लिए विकास की मांगों को आकार देने और उसमे उपयोग किए जाने वाली अध्यक्षता के लिए कार्यरत है। इन दिनों, सिविल सोसाइटी संगठनों, सामाजिक विकास कार्यकर्ताओं और विकास सम्बन्धी पेशेवरों द्वारा सिविल ब्रिक्स फोरम का सक्रिय रूप से अनुसरण किया जा रहा है ताकि सामाजिक-आर्थिक अंतराल पर प्रकाश डाला जा सके, जिन पर वित्तपोषण, नीति सुरक्षा उपायों और सामाजिक भागीदारी के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। समाज सेवी क्षेत्र की भागीदारी और उसके संस्थापन पर चर्चा एवं उसे मजबूत बनाने के लिए सिविल ब्रिक्स मंच को एक आदान प्रदान और साझेदारी मंच के रूप में सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा कई प्रयास किए गए हैं।[2] जैसा कि भारत इस बहुपक्षीय संगठन की अध्यक्षता में शामिल है, सिविल सोसाइटी क्षेत्र राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय संदर्भों में मजबूत निर्णयों में सुझाव देने के लिए तैयार है। 2016 में, पांच देशों की सिविल सोसाइटी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि भारत सरकार ने सिविल ब्रिक्स भागीदारी का स्वागत किया था और सिविल सोसाइटी संगठनों के सुझावों को सुना था । हालाँकि, अधिकांश सुझावों को सिविल ब्रिक्स नेता ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन सिविल सोसाइटी के हितों को जोड़ा गया और स्थानीय सुनवाई के लिए मतदाताओं को सुनिश्चित किया गया। 2021 में भारत में ब्रिक्स की मेजबानी के रूप में वही मनोभाव उजागर हो रहा है। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जिसे अन्य ब्रिक्स देशों के बीच बहुपक्षीय एजेंडा में सामाजिक विकास पहलुओं की चर्चा और एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित किया जा सकता है।

---

[1] Poskitt, A.; Shankland, A. and Taela, K. (2016) Civil Society from the BRICS: Emerging Roles in the New International Development Landscape, IDS Evidence Report 173, Brighton: IDS

[2] PRIA (2013). India's Global Development Presence and Engagement of Indian Civil Society. from : http://www.pria.org/docs/Indias_Global_Development_Presence_and_Engagement_of_Indian_Civil_Society.pdf

जैसा कि सभी बहुपक्षीय और सहभागिता समूहो से अनुभव होता है, यह उम्मीद की जा रही है कि विकास लक्ष्य केवल एजेंडा बयानबाजी तक ही सीमित नहीं हो बल्कि स्पष्ट रूप से परिभाषित नीति उपकरणों के माध्यम से स्थानीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर संकल्पित किए जाये । विनाशकारी कोविड -19, जिसने सामाजिक-विकास को हर प्रकार से रोक दिया है, ऐसे में भारत सरकार के साथ सिविल सोसाइटी से अपेक्षा कई गुना बढ़ जाती है और यह अपने निर्णयकर्ताओं को दीर्घकाल में विकास से जोड़कर अपने अध्यक्ष पद में अपनाए गए समयबद्ध लक्ष्यों को बनाये रखने की मांग करती है। दूसरा, संचालन के हर स्तर पर समाज सेवी क्षेत्र के साथ एक संस्थागत भागीदारी अपनाने की जरूरत है - नीति निर्माण में भागीदारी और वित्तीय सहायता तथा स्वैच्छिक संगठनों को प्रभावी रूप से विकास के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना आदि। इसलिए, यह नीति दस्तावेज सिविल ब्रिक्स के भारतीय अध्यक्षता द्वारा अपनाए गए लक्ष्यों की जांच करता है- विकास के लिए वित्त, ग्लोबल पब्लिक गुड्स (वैश्विक सार्वजनिक सामान), महामारी पर प्रतिक्रिया और सिविल सोसाइटी के साथ साझेदारी तथा सिविल सोसाइटी (समाज सेवी क्षेत्र) की विकास मांगों को रेखांकित करता है। यह दस्तावेज़ वाणी द्वारा तैयार किया गया है, जिसने जमीनी स्तर की सामाजिक गतिविधियों, स्वैच्छिक संस्थानों और सिविल सोसाइटी नेटवर्क के साथ अपने वर्षों के परामर्श को इकट्ठा करके बनाया है

भारत के विकास में भारतीय सिविल सोसाइटी की भूमिका

70 वर्षों में स्वयंसेवी क्षेत्र, भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में हस्तक्षेप द्वारा उसका स्तर ऊपर उठाने में सहायक रहा है, जो विकास की गति में रूकावट लाते हैं। इसके साथ ही, यह निर्णायक संस्थानों को प्रभावित करने में और वंचित नागरिकों की सुनवाई के लिए एक सूत्रधार रहा है। समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संस्थानों में 'सामाजिक परिवर्तन' के प्रोटोटाइप और दृष्टिकोण तैयार किये गए, जिससे समाज के सबसे छोटे स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसने इस क्षेत्र को मानवीय कार्यो और विभिन्न विकास पहलुओं पर ज्ञान के भंडार के रूप में सम्मानित किया है। इन स्वैच्छिक क्षेत्रो में विकास सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं और नीतियों में उनके समाधानों का स्पष्ट सह-चयन देखा गया है। स्वैच्छिक संगठन निर्णायक हस्तक्षेप का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके लिए उनके सामाजिक नए विचार, सरलता और कल्पना के लिए सराहना की गई है।[3] उनके हस्तक्षेपों का लोगों के जीवन को प्रभावित करने और परिवर्तनशील बदलाव लाने में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर स्वीकारने योग्य है। उनके प्रयासों की मान्यता, लाखों भारतीय स्वयं सेवी संस्थानों में विश्वास को व्यक्त करता हैं, जो संचालन मंडल के साथ बातचीत में उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें। सामूहिक रूप से भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र विभिन्न सामाजिक-विकास चुनौतियों का सामना कर रहा है जैसे गरीबी उन्मूलन, असमानता के अंतराल को कम करना, समावेशी विकास, लिंग संतुलन और कमजोर वर्ग की सुनवाई करना।[4] जमीनी स्तर पर अपने सुसंगत इंटरफेस के माध्यम से, समाज सेवी संस्थान रीयल-टाइम डेटा एकत्र करते हैं जिसका उपयोग वे विभिन्न मजबूत संरचनाओं के पक्ष समर्थन के लिए करते हैं। इसके आधार पर, समाज सेवी संस्थान आधुनिक सामाजिक मॉडल और क्रॉस-डिसिप्लिनरी (दूसरे क्षेत्रों में) प्रतिमानों का निर्माण कर रहे हैं, जिन्होंने प्रचलित यथास्थिति में प्रगतिशील परिवर्तन किए हैं।

[3] The Role of CSOs in_2050and Beyond, Contribution from UNESCO's Collective Consultation of NGOs on Education 2030 to UNESCO's Futures of Education Initiative March 2021

[4] AN ANALYTICAL STUDY ON THE ROLE OF NGOs IN THE POVERTY REDUCTION OF INDIA Dr. R. Uma Devi, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Dr. S. R. K. Govt. Arts College, Pondicherry University, Yanam, India.

कोविड -19 राहत कार्य

भारतीय सिविल सोसाइटी संगठन दो कारकों के रूप में कोविड-19 महामारी का सक्रिय रूप से जवाब दे रहे हैं - स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और उनसे संबंधित सामग्री जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र आदि और लॉकडाउन से प्रभावित गरीब आबादी का सहयोग करना।[5] सरकार द्वारा संक्रमण को कम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से कारखानो में अस्थायी निलंबन के कारण दैनिक मजदूरों और श्रमिक वर्गों के लिए आर्थिक चुनौतियां पैदा हो गयी । इसके कारण कारखाने के श्रमिकों, दैनिक मजदूरों ने बड़े पैमाने पर पलायन किया चूँकि लॉकडाउन की अवधि में सार्वजनिक परिवहन बंद थे, कई सिविल सोसाइटी संगठनों ने देश के शहरों और प्रमुख राजमार्गों में व्यापक भोजन वितरण, राशन सुविधा, आश्रय की व्यवस्था की।[6] विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान, कई संगठनों ने सीमित वित्तीय और मानव संसाधनों के बावजूद राहत प्रदान करने के लिए कार्य किया। कर्तव्य के क्रम में इस क्षेत्र ने 120 सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं और प्रतिभागियों को खो दिया है।[7]

सिविल ब्रिक्स - विकास सहयोग में सिविल सोसाइटी से वार्तालाप के लिए एक मंच के रूप में

अन्य सभी बहुपक्षीय समूहों की तरह, ब्रिक्स ने सिविल सोसाइटी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को सामाजिक मुद्दों पर प्रतिनिधित्व करने और मजबूत विकास नीति निर्माण के लिए सुझाव देने के लिए एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया है।[8] भारतीय विकास सहयोग ने लंबे समय तक अपनी योजनाओ और नीतियो में सिविल सोसाइटी के इनपुट को सम्मिलित नहीं किया था। इसे फोरम फॉर इंडियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन (एफआईडीसी) की स्थापना द्वारा संबोधित किया गया, जिसने भारत सरकार के साथ सहयोग रणनीतियों को विकसित करने में एक सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करके इस ज्ञान की कमी को पूरा किया। 2016 में जब सिविल ब्रिक्स का उद्घाटन हुआ, तब सिविल सोसाइटी को आदान-प्रदान और सरकार के साथ भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऐतिहासिक क्षण प्रदान किया गया। वास्तव में, यह 2021 तक पूरे जोश के साथ जारी रहा और सिविल ब्रिक्स के विभिन्न आयोजनों में इस क्षेत्र की भागीदारी को देखा गया। स्वैच्छिक क्षेत्र के रूप में, हम ब्रिक्स देशों से इस मंच को पूरा महत्व देने की अपील करते हैं क्योंकि यह -

1) ग्लोबल साउथ के लिए एक आवाज- विकास परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत बनाये रखने के लिए और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के सिद्धांतों की अभिव्यक्ति, जो व्यापार, निवेश, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी विनिमय के साथ-साथ लोगों के बीच संबंधों को प्राथमिकता देती है।[9]

2) उपेक्षित लोगों के लिए सहयोग मंच- तेजी से आर्थिक परिवर्तन के बावजूद सदस्य देशों जैसे ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ठ गरीब आबादी है।[10] उनमें से कई लोगों को सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रयासों से विभिन्न राहत सामग्री दी गयी । ब्रिक्स सिविल फोरम में भाग लेकर ये संगठन वास्तव में इन उपेक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं

[5] Weaker and poorer, NGOs still the best bet in delivering Covid-19 reliefhttps://www.business-standard.com/article/companies/weaker-and-poorer-ngos-still-the-best-bet-in-delivering-covid-19-relief-120042800370_1.html

[6] Coronavirus in India: In 13 states, NGOs fed more people than govt did during lockdownhttps://www.indiatoday.in/india/story/in-13-states-ngos-fed-more-people-than-govt-during-coronavirus-lockdown-1665111-2020-04-09

[7] Data collected by VANI

[8] http://civilbrics.ru/wp-content/uploads/2020/03/Concept2020eng.pdf

[9] John L, Engaging BRICS Challenges and Opportunities for Civil Society, Oxfam India Working Papers Series, 2012

[10] Technology, Poverty and Education within BRICS Context, KunofiwaTsaurai, Bester Chimbo, International Journal of Economics and Business Administration Volume VIII, Issue 4, 2020

3) सिविल सोसाइटी के आदान-प्रदान के लिए एक संघ - सिविल सोसाइटी के अनुभवो को साझा करने से नई विकास योजनाओं को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, जिनका उपयोग सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा उनकी राहत गतिविधियों में सहायता के लिए किया जाता है। जैसे - नई सोच और मंथन में मंच सहायता करता है, जिसे नीति निर्माताओं और शेरपाओं के साथ भी साझा किया जाता है।

4) एसडीजी और विकास वित्तपोषण के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच- सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए विकास प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन विकास लक्ष्य महत्वपूर्ण साधन हैं। सिविल ब्रिक्स एसडीजी की उपलब्धि में सहयोग के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धताये उनकी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने और सहयोग करने की ओर ध्यान आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक को विकास वित्तपोषण का काम सौंपा गया है जो सिविल सोसाइटी के नीति अवलोकन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

5) आपातकालीन राहत कार्यो के समय भागीदारी के लिए क्षेत्र - हाल ही में कोविड -19 के अनुभव ने दुनिया भर की सरकारों को महामारी को कम करने में कठिन राहत कार्यों के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रति अधिक विचारशील होने के लिए संवेदनशील बनाया। इस प्रकार, ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय समूह सहयोग समूहों से तत्काल आपातकालीन राहत कार्य विकसित करने, बेहतर नीति समन्वय के लिए साझेदारी और अनुभव प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता एजेंडे को सिविल सोसाइटी की विकास मांगों से जोड़ना

ब्रिक्स में भारतीय अध्यक्षता ने ब्रिक्स के इस वर्ष के अपने फोकस को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, जो ब्रिक्स@15 के विषय में परिलक्षित होता है: निरंतरता, एकीकरण और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग विभिन्न आम चुनौतियों और सहयोग के क्षेत्रों से पहले है, जो आने वाले वर्षों में ब्रिक्स की फिलोसफी को मजबूत करने में मदद करेगा।[11] सिविल सोसाइटी से सम्बंधित एजेंडे के बिंदु नीचे दिए गए हैं-

बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार

भारत कई वर्षों से वैश्विक बहुपक्षीय तंत्र जैसे यूएनएससी, डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक / अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सुधार की मांग कर रहा है। इनमें से अधिकांश मंच ग्लोबल नार्थ की ओर उन्मुख है और उन्होंने ग्लोबल साउथ को संतुलित प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया है। महत्वपूर्ण रूप से यह नोट किया गया था कि बहुपक्षीय संगठनों को और अधिक सुदृण बनाने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली का रूप सार्वभौमिक स्वतंत्रता, समानता, पारस्परिक वैध हितों और चिंताओं का सम्मान करते हुए सभी के लाभ के लिए समावेशी परामर्श और सहयोग पर आधारित होना चाहिए।[12] जैसा कि नोट किया गया है की अन्य विख्यात देशो की तरह भारत ब्रिक्स देशों के साथ वैश्विक संचालन के निर्णय लेने में अधिक समावेश की मांग कर रहा है। हालाँकि, सिविल सोसाइटी सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के नीति-निर्माण और वितरण में समान रूप से समावेशन चाहता है।

[11] Inaugural Address at BRICS Civil Forum 2021 by Secretary (CPV&OIA) and BRICS Sherpahttps://www.mea.gov.in/SpeechesStatements.htm?dtl/33808/Inaugural_Address_at_BRICS_Civil_Forum_2021_by_Secretary_CPVOIA_and_BRICS_Sherpa

[12] https://www.deccanherald.com/national/india-china-other-brics-nations-make-a-joint-push-for-reform-of-multilateral-system-992751.html

सिविल सोसाइटी की मुख्य मांग: स्थानीय और वैश्विक स्तर पर नीतिगत निर्णयों में समावेशी भागीदारी

भारतीय सिविल सोसाइटी संगठन विभिन्न प्रकार की विकास राहत गतिविधियों में शामिल हैं और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के प्रबंधन और उन्हें कम करने में अनुकरणीय उत्कृष्टता रखते हैं। सरकार के साथ और कभी-कभी सहयोग में काम करते हुए, इनमें से कई संगठनों ने उप-राष्ट्रीय नीतियों को विकसित करने में मदद की है, जिन्होंने उनकी योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में सरकारी प्रयासों को सहायता प्रदान की है। उदाहरण के लिए, सिविल सोसाइटी संगठनों ने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, कुछ फसलों की कटाई से किसानों की आय बढ़ाने, गांवों के विद्युतीकरण के लिए सौर पंप और पैनल विकसित करने, ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आजीविका रोजगार देने, स्थायी आवास प्रदान करने, पानी के अधिशेष क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रभावी परियोजनाएं विकसित की हैं। - दुर्लभ क्षेत्र, पंचायतों (ग्राम परिषदों) और नगर पालिकाओं के शासन में नागरिकों की क्षमता विकसित करना, बच्चों को रियायती शिक्षा प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, खेल सुविधाएं प्रदान करना और युवा विकास आदि।

अपने कार्य और अनुभव के आधार पर, सिविल सोसाइटी संगठनों के पास राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने वालों के साथ बातचीत करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। विकास परिषद या समाज सेवी क्षेत्र प्रतिनिधित्व के लिए प्रमुख कार्यक्रम समिति की कमी कई योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिकूल रही है। क्योंकि वे जमीनी स्तर पर आधारित हैं, सिविल सोसाइटी संगठनों को जमीनी स्तर पर वितरण योजनाओं का अनुभव भी है। उदाहरण के लिए, कोविड -19 में इन संगठनों ने भोजन, आवश्यक वस्तुएं और दवाएं पहुंचाईं, जहां सरकार नहीं पहुंच सकी। इसी तरह के अनुभव राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के साथ हैं , जहां वे सिविल सोसाइटी की सेवाओं पर भरोसा करते हैं। इस प्रकार, सिविल सोसाइटी द्वारा एकत्रित ज्ञान और अनुभव, का उपयोग नीति निर्माण में किया जा सकता है। ऐसे में सिविल सोसाइटी राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर इन कार्रवाई बिंदुओं को लागू करने के लिए ब्रिक्स में भारतीय अध्यक्षता के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव दे रही है-

1) विकास पर सिविल सोसाइटी प्रतिनिधित्व के लिए समावेशी मंच संस्थान /समितियां[13]: यह देखते हुए कि यह संचालन में मदद करेगा और नीति के लिए महत्वपूर्ण इनपुट और आकलन प्रदान करेगा, योजनाओं पर सरकारी कार्रवाई- एक डिफ़ॉल्ट संस्थागत मंच की आवश्यकता है जहां सभी प्रकार के सिविल सोसाइटी संगठनों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता हो।

2) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तीय सहायता प्रदान करना- सिविल सोसाइटी संगठन कुटिल प्रबंधकीय संस्थाएं हैं जिन्हें सामाजिक विकास में विशेषज्ञता प्राप्त है। वित्तीय बाधाओं के कारण उनका विकास अवरुद्ध हो रहा है, यह उपयुक्त होगा कि सरकार सरकारी अनुदानों और निधियों के माध्यम से सिविल सोसाइटी संगठनों की मदद करे और सहयोग करे जिससे योजनाओं के वितरण समय में मदद होगी।

3) सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करना - सरकार को सिविल सोसाइटी के लिए एक अनुकूल नियामक व्यवस्था प्रदान करने की आवश्यकता है जो उन्हें नियामक अनुपालन और निरिक्षण के बोझ के बजाय उनकी प्राथमिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी।

वैश्विक स्तर पर

भारत के रणनीतिक विकास सहयोग को इसके विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ जोड़ा गया है, जिसे आर्थिक विकास द्वारा बढ़ावा दिया गया है जो इसे राजनीतिक प्रभाव वाली एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति बनाने के लिए जिम्मेदार है। भारत ब्रिक्स (2021) जी-20 (2023) की मेजबानी करने और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी कई वैश्विक पहलों का नेतृत्व करने के लिए प्रमाणित रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दुनिया को साझा समृद्धि की ओर बढ़ने और आम चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया

[13] Improving Global Governance Through Engagement With Civil Society, The case of BRICS, Oxfam Briefing Note, March 2016

है। यह एक वैश्विक संचालन ढांचे को विकसित करने की दिशा निर्देशित करता है जहां जमीनी स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की सामाजिक विकास की चुनौतियों के लिए ठोस समाधान तैयार किए जाते हैं। बहुपक्षीय मंचों पर समावेशी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के प्रयास में सिविल सोसाइटी विभिन्न मंचों पर भाग ले रहा है। उदाहरण के लिए, भारतीय सिविल सोसाइटी गरीबी, वित्त पोषण, विकास नीतियों आदि पर वैश्विक चर्चाओं में सिविल 20 (सी-20) और सिविल ब्रिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही है। यह केवल तभी उपयुक्त है जब भारत अपने आह्वान के आधार पर वैश्विक राजनीति में एक सक्रिय स्थान प्राप्त करता है। बहुपक्षीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई जिसके लिए इन वैश्विक संचालन व्यवस्थाओं में भाग लेने के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों को स्थान और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

एसडीजी की उपलब्धि के लिए डिजिटल और तकनीकी समाधानों का उपयोग करना

भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों ने दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी समाधानों के महत्व को रेखांकित किया है। भारत ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए डिजिटल ज्ञान का उपयोग करने की ओर बढ़ रहा है जो स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों[14] और अन्य विषयों में आपूर्ति की कमी को दूर करने में मदद करेगा। भारत ने दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को उत्साहपूर्वक अपनाया और मानकों पर प्रगति को मापने के लिए हर साल अपनी बेसलाइन इंडेक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करता आ रहा है । डिजिटल विद पर्पस: डिलीवरिंग ए स्मार्टर 2030 रिपोर्ट के अनुसार, "*डिजिटल तकनीकें सकारात्मक सामाजिक मूल्य में अग्रणी योगदानकर्ता हो सकती हैं, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है, जब तकनीकी विकास और उसका संचालन केंद्रित दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता द्वारा तैयार किया गया हो। यदि आईसीटी क्षेत्र दुनिया को दिखा सके कि वह 2030 एजेंडा की ओर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है और नकारात्मक परिणामों को संबोधित करने और रोकने की जिम्मेदारी लेता है, तो दुनिया को काफी लाभ होगा और इस क्षेत्र को दीर्घकालिक सफलता का आश्वासन मिलेगा ।*[15]

अधिकांश देशों द्वारा दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकि का उपयोग करने का कदम उठाया गया है, हालांकि, मोबाइल टेलीफोन को बढ़ाकर लाभार्थियों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकि को और अधिक सुलभ बनाने की आवश्यकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) एसडीजी 3 की प्रगति के निरिक्षण में आवश्यक हैं: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, एसडीजी 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एसडीजी 9: बुनियादी ढांचा, औद्योगीकरण और नवाचार। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एसडीजी की उपलब्धि के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका एसडीजी की दिशा में प्रगति करने के लिए महत्वपूर्ण है। रीयल-टाइम ट्रैकिंग के माध्यम से प्रगति को सक्षम और प्रबंधित करने के लिए, भारी मात्रा में डेटा एकत्र करने और संसाधित करने की आवश्यकता है। यह प्रसंस्करण, बदले में, डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे पर नई मांगें पैदा करता है। गीगाबिट नेटवर्क पहले से कहीं अधिक उच्च गति, कम विलंबता की विशेषता वाले बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हैं, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।[16]

इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्रौद्योगिकि का उपयोग संकेतकों पर डेटा के निरिक्षण और सरकारों को रीयल टाइम फीडबैक प्रदान करने और एसडीजी 17 के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संचालन को प्राप्त करने में सहायता के लिए किया जा सकता है।

[14] High Performance Computing (HPC) and Information Communication Technologies (ICT) discussed at BRICS Working Group MeetingPosted On: 30 MAY 2021 9:56AM by PIB Delhihttps://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1722819

[15] https://gesi.org/platforms/digital-with-a-purpose-delivering-a-smarter2030

[16] http://sdghelpdesk.unescap.org/knowledge-hub/thematic-area/digital-technologies-for-sdgs/

सामाजिक भलाई के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता से हानि

- जब भारत सरकार एसडीजी से जुड़ने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रही थी - देश भर में केवल 23.8% परिवारों के पास इंटरनेट की पहुंच थी। इसके अतिरिक्त, शहरी और ग्रामीण परिवारों के बीच पहुंच में व्यापक अंतर है। ग्रामीण समुदायों में रहने वाली भारत की 66% आबादी में से 42% शहरी परिवारों की तुलना में केवल 14.9% के पास इंटरनेट है।[17]

- 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग, में यह नोट किया गया था कि केवल 20% आबादी ही इंटरनेट का उपयोग कर सकती है। अन्य कारकों के साथ-साथ उम्र, स्थान, लिंग, जाति और भाषा के संदर्भ में भी इंटरनेट तक पहुँच और उपयोग करने में असमानता मौजूद है।[18]

- संयोग से डिजिटलीकरण में वृद्धि के साथ नकली समाचारों में आनुपातिक वृद्धि हुई। सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 30% भारतीयों ने कोविड -19 जानकारी के लिए व्हाट्सप्प का उपयोग किया, और लगभग 50% से कम संदेशों को फ़ॉरवर्ड करने से पहले फ़ैक्ट चेक किया। 13% उत्तरदाताओं ने यहां तक कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने से पहले कभी भी संदेशों की तथ्य-जांच नहीं की। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश उपयोगकर्ता पलायन के लिए ज़िम्मेदार थे, हालाँकि, केवल 14% ने एक दिन में तीन या अधिक संदेशों को फॉरवर्ड किया, और केवल 5% ने नौ या अधिक संदेशों को फॉरवर्ड किया।[19]

- ब्रिटेन स्थित मार्केट रिसर्च फर्म यूगोव और नैसडेक लिस्टेड एसीआई वर्ल्डवाइड के एक अध्ययन के अनुसार, डिजिटलीकरण में वृद्धि ने डिजिटल लेनदेन में विविध समस्याओं को भी जन्म दिया है, लगभग आधे से ज्यादा भारतीय उपभोक्ता डिजिटल भुगतान से जुडी धोखाधड़ी के बारे में चिंतित हैं, जब से कोरोना वायरस के कारण डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी हुई।[20]

- भारत सरकार ने जैम ट्रिनिटी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभार्थी स्थानान्तरण प्रदान करने की मांग की है।[21] इंडस एक्शन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में लाभार्थियों की राशन, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार की स्थिति और सरकारी योजनाओं तक पहुंच का आकलन किया गया। जन धन के लिए पात्र 2,233 महिलाओं में से केवल 59% ने बताया कि उन्हें लाभ मिला है। जबकि 34% ने कहा कि उन्हें स्थानांतरण नहीं मिला, 7% ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें लाभ मिला है या नहीं।[22]

- कोविड से संबंधित लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण ई-लर्निंग में उछाल उन बच्चों पर भी देखा गया जो स्कूल नहीं जा सकते थे। 75% से अधिक बच्चों ने खराब या इंटरनेट कनेक्शन न होने, अफोर्डेबल डेटा पैक, धीमी इंटरनेट स्पीड आदि के कारण ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुँचने में कई चुनौतियों के बारे में बताया ।[23]

---

[17] Digital Divide in India ,https://www.borgenmagazine.com/digital-divide-in-india/

[18] The digital divide in India: How access to technology and reliable information affects India's response to the pandemichttps://www.apc.org/en/node/37367

[19] The Impact of Social Media on Panic During the COVID-19 Pandemic Journal of Medical Internet Research

[20] https://www.financialexpress.com/economy/alert-digital-payments-fraud-shoots-up-as-consumers-prefer-upi-cards-amid-coronavirus-lockdown-cases-rise-this-much-in-a-month/1968230/

[21] JAM (short for Jan Dhan-Aadhaar-Mobile) trinity refers to the government of India initiative to link Jan Dhan accounts, mobile numbers and Aadhaar cards of Indians to plug the leakages of government subsidies

[22] https://www.indiaspend.com/40-of-jan-dhan-account-holders-could-not-access-govts-covid-19-relief-survey/

[23] https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/over-75-children-report-challenges-to-access-education-digitally-survey/articleshow/82050164.cms

एसडीजी में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सिविल सोसायटी की मांग

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार "प्रौद्योगिकि हमारी दुनिया को निष्पक्ष, अधिक शांतिपूर्ण और अधिक न्यायपूर्ण बनाने में मदद कर सकती हैं। डिजिटल प्रगति द्वारा 17 दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों में से प्रत्येक की उपलब्धि के लिए सहयोग और वृद्धि लाई जा सकती है - अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने से लेकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने, स्थायी खेती और सभ्य कार्य को बढ़ावा देने और सर्व साक्षरता प्राप्त करने तक। लेकिन प्रौद्योगिकि गोपनीयता को भी खतरे में डाल सकती हैं, सुरक्षा और साधनो में असमानता हैं। मानव अधिकारों और मानव एजेंसी के लिए उनके निहितार्थ हैं।[24]"

बढ़ते विकास से सीधा संबंध: ग्लोबल इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव (जीईएसआई) और डेलॉइट की एक नई रिपोर्ट "डिजिटल विद पर्पस: डिलीवरिंग ए स्मार्टर 2030" के अनुसार : यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे प्रौद्योगिकि सरकारों, व्यवसायों और परोपकारी संगठनों को 17 दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के अपने प्रयासों में तेजी लाने में मदद कर सकती हैं। 20 विशेष लक्ष्यों और 25 संबद्ध संकेतकों सहित एसडीजी लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के इसके विश्लेषण से पता चलता है कि मौजूदा डिजिटल प्रौद्योगिकि और उसके कार्योन्वयन, औसतन, एसडीजी की प्रगति में 22% की तेजी लाने और नीचे की प्रवृत्ति को 23% तक कम करने में मदद करेगी।[25]

भारत में सिविल सोसाइटी कुछ सिफारिशों को सूचीबद्ध कर रहा है जिन्हें देश में डिजिटलीकरण में सुधार के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए-

- मोबाइल टेलीफोनी और डिजिटल पहुंच में वृद्धि- डिजिटल इंडिया के अनुरूप, सिविल सोसाइटी डिजिटल बुनियादी ढांचे में सही निवेश करना चाहता है जिससे देश भर में दूरसंचार के उपयोग और प्रसार में वृद्धि होगी। इसके लिए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी बढ़ाना और दूरसंचार क्षेत्र में कर को कम करना आवश्यक है।[26] हालांकि, डिजिटलीकरण में वृद्धि और नागरिक निरिक्षण के बीच सीधा संबंध है[27]
- सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण को आसान बनाना और ई-गवर्नेंस को सुगम बनाना - डिजिटलीकरण का एक महत्वपूर्ण कार्य यूजर इंटरफेस एप्लिकेशन के माध्यम से नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं और सामानों की डिलीवरी करना है। हालाँकि, ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका नागरिकों को निरंतर सेवाएं प्रदान करने के लिए समाधान किए जाने की आवश्यकता है। संवेदनशील सूचकांकों और मापदंडों के अनुसार आबादी की पूरी तरह से मैपिंग करना जिससे आबादी को सीधे सार्वजनिक सामान पहुंचाने में मदद मिल सकती है।[28]
- डिजिटल निरक्षरता के अंतराल को ख़त्म करना - भारत एक बड़ा देश है जहां लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आबादी का लगभग 30% निरक्षर है (जनगणना: 2011) और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्र और बिहार, उड़ीसा और यूपी जैसे कम विकसित राज्यों के मामले में यह अधिक है। दूसरे, इंटरनेट पर अंग्रेजी का प्रभुत्व मुख्य बाधा है क्योंकि भारत

[24] https://www.un.org/en/un75/impact-digital-technologies

[25] https://deloitte.wsj.com/cio/2019/09/23/digital-tech-critical-to-u-n-sustainable-development-goals/

[26] Dua, Bindu, Digital India-Challenges and Suggestions, Mier College of Education, 2018

[27] Hagen J,Lysne, O ,Protecting the digitized society—the challenge of balancing surveillance and privacy, Cyber Defense Review, Vol. 1, No. 1 (SPRING 2016), pp. 75-90

[28] https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/still-many-challenges-in-ensuring-dbt-benefits-reach-women-niti-aayog-advisor/articleshow/65581981.cms?from=mdr

के मामले में 80% से अधिक आबादी अंग्रेजी नहीं बोलती है (जनगणना: 2011)। कंप्यूटर और इंटरनेट पर अंग्रेजी के इस तरह के अत्यधिक प्रभुत्व के कारण भारतीय गांवों में यह पहुंच योग्य नहीं है। तीसरा, प्रशासनिक संस्कृति ऐसे उपायों के लिए अनुकूल नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि देश में अमीर और गरीब क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन है।[29] इसके लिए यह सिफारिश की जाती है कि सरकार सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ साझेदारी मॉडल अपनाए जो ग्रामीण आबादी को आईसीटी के उपयोग से परिचित कराने में मदद करने के लिए डिजिटल साक्षरता पर काम कर रही हैं।

- गोपनीयता, सुरक्षा और साइबर-अपराध को कम करना - सरकार और सिस्टम इंटीग्रेटर्स को अत्याधुनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल (जैसे 256-बिट एईएस एन्क्रिप्शन, आदि) के आवेदन को सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार द्वारा सम्बंधित गोपनीयता नीतियां स्थापित की जानी चाहिए ताकि उन लोगों द्वारा जानकारी का दुरुपयोग न किया जाए जिनके पास इसकी पहुंच है।[30] जबकि भारत ने अन्य देशों से सीखकर साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून अपनाए हैं,[31] सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ साझेदारी विकसित करने की आवश्यकता है।[32] जो साइबर अपराधों और धोखाधड़ी को रोकने में काम कर रहे हैं। कई सिविल सोसाइटी संगठन[33] अब साइबर धोखाधड़ी और अपराधों का पता लगाने के लिए नागरिकों की क्षमता निर्माण का काम कर रहे हैं।
- एआई-कार्यक्रम विकास योजनाओं के लिए सिविल सोसाइटी विशेषज्ञता का उपयोग करना- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है, अनुभव और अपेक्षाओं से आशंकित नागरिकों के निर्णय एवं व्यवहार पैटर्न आधारित विकास नीतियां सहायक हो सकती है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एसडीजी नीतियों को विकसित करने के लिए फायदेमंद हो सकती है।[34] ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें एआई का उपयोग करके तकनीकी आधुनिकता वर्तमान विकास कार्यों में सुधार के लिए बड़ी संभावनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एआई स्वास्थ्य डेटा के आधार पर आबादी का सर्वेक्षण करने और पूर्वानुमान करने में मदद कर रहा है, और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और चिकित्सकों को बीमारियों के निदान और उपचार के लिए दक्षता प्रदान कर रहा है। कृषि क्षेत्र में, एआई किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु और फसल के स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो सके और उन जोखिमों को कम किया जा सके जो उनकी फसल ख़राब कर सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में, एआई तीन प्रमुख क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है: विद्यार्थी की प्रौद्योगिक चुनौतियां (जैसे व्यक्तिगत डिलीवरी मॉडल और अनुकूल शिक्षण प्लेटफॉर्म), शिक्षक की प्रौद्योगिक चुनौतियां (स्वचालित उपकरण मूल्यांकन) और क्षेत्र-स्तरीय विश्लेषण (उदाहरण के लिए स्कूल निरीक्षण प्रदर्शन का पूर्वानुमान करने के लिए सभी स्कूलों के डेटा का उपयोग करना)।[35] सिविल सोसाइटी संगठन कई डेटा-सेट के साथ काम कर रहे हैं जो विकास कार्यक्रमों और योजनाओं को डिजाइन करने के लिए लाभार्थियों से एकत्र किए गए अपने निष्कर्षों को इनपुट करते हैं। इससे लागत, निवेश और समय की बचत होगी। प्रभावी रूप से यह विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों को लक्षित करने और गोपनीयता को बनाये रखने में मदद करेगा।[36]

[29] Beniwal, V.S., Sikka, Kapil, E-Governance in India: Challenges and Prospects, International Journal of Computer and Communication, 2017

[30] E-governance and Digital India Empowering Indian Citizens Through Technology, ASSOCHAM, 2015

[31] Securing the Nation's Cyber Space, Price Waterhouse Coopers (PwC), 2017, https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2017/securing-the-nations-cyberspace.pdf

[32] https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/taking-action-where-we-can-to-stop-cybercrime.html

[33] https://yourstory.com/socialstory/2020/07/social-media-awareness-cybercrime-bullying/amp

[34] Ricardo Vinuesa, Hossein Azizpour, IolandaLeite, Madeline Balaam, Virginia Dignum, Sami Domisch, Anna Felländer, Simone Daniela Langhans, Max Tegmark & Francesco Fuso Nerini, The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals, Nature Communications, 2020

[35] The International Development Innovation Alliance (IDIA). (2019). Artificial intelligence in International Development. A discussion paper

[36] https://www.weforum.org/agenda/2018/04/civil-society-charities-artificial-intelligence/

- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना - ब्लॉकचैन भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों की गेम चेंजर बनने की क्षमता रखता है। इसकी सफलता और असफलता काफी हद तक सम्बंधित तत्वों पर निर्भर करती है - संरचना, कानूनी प्रणाली, सामाजिक अथवा राजनीतिक स्थापना आदि, यह केवल प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर नहीं करता।[37] ब्लॉकचेन सूचना की सुरक्षा और प्रमाणिकता सुनिश्चित करके समस्या का समाधान करना चाहता है, इस समय जब डेटा गोपनीयता और सरकार में विश्वास में कमी की चिंता बढ़ रही है। यह एक ऐसी तकनीक है जो जानकारी को प्रमाणित करने के लिए एक केंद्रीय आधिकरण के बिना डेटा की पारदर्शिता, प्रमाणिकता और ट्रैकिंग की क्षमता सुनिश्चित करते हुए, संपत्ति को रिकॉर्ड करने, मूल्य हस्तांतरण और विकेन्द्रीकृत तरीके से लेनदेन को ट्रैक करने की अनुमति देती है। यह अनिवार्य रूप से सूचना और साझा डेटाबेस को एन्क्रिप्ट करने के लिए एक प्रणाली है। यह जानकारी को प्रमाणित करने और लेनदेन को मान्य करने के लिए विश्वसनीय पार्टियों के बीच एक आम सहमति तंत्र पर आधारित है। ब्लॉकचेन में दो विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण बनाती हैं। सबसे पहले, यह सूचना की सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व स्तर प्रदान करता है और रिकॉर्ड की प्रमाणिकता को प्रबंधित करता है, उसकी प्रामाणिकता की गारंटी भी देता है। यह डेटा के प्रबंधन में मुश्किलों और जोखिमों के अवसरों को समाप्त करता है। यह अधिकारी तंत्र में डेटा समस्याओ को दूर करने में भी मदद करता है जिसमें सार्वजनिक संस्थाएं आपस में जानकारी साझा करने के लिए अनिच्छुक हैं।[38] भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने का एक प्रमुख उदाहरण आंध्र प्रदेश राज्य है जो नागरिकों की संपत्ति का पंजीकरण करते समय नक़ल को दूर करता है, निजी डेटा को सुरक्षित करता है। ऐसी तकनीकों का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में किया जा सकता है, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ प्रदान करने में।[39] खुली और पारदर्शी, डिजिटल निरिक्षण प्रणाली संरचना परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को कम करने में मदद कर सकती है और परियोजनाओं को समय पर डिलीवर (वितरित) करने में प्रभावी हो सकती है।[40]

- एसडीजी डेटा के लिए डिजिटल डैशबोर्ड बनाना - सिविल सोसाइटी क्षेत्र के साथ स्केपिंग - लाभार्थियों और समुदायों का डेटा बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसे भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एसडीजी योजनाओं में एकीकृत करने की आवश्यकता है। जैसे, एसडीजी कार्यान्वयन में सिविल सोसाइटी का समावेश महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कई चुनौतियों और समाधानों को प्रकट करते हैं जिनका उपयोग नीति और संकेतकों की प्रगति के निरिक्षण के लिए किया जा सकता है।[41] ऐसी कई एजेंसियां और संस्थान हैं जो देश और वैश्विक स्तर पर एसडीजी के निरीक्षण के लिए डेटा विज़ुअलाइज़ेशन में सिविल सोसाइटी और सरकारों से डेटा एकत्रित कर रहे हैं।[42] सरकार पहले ही कई प्रकार के उपयोगों के लिए एक डैशबोर्ड बनाने की प्रक्रिया में कार्यरत है। ऐसा ही एक डैशबोर्ड नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल है, जो विकास लक्ष्यों के लिए सीएसआर खर्च के लिए हीट मैप, प्रोजेक्ट सहयोग, लर्निंग एक्सचेंज और डेटा ट्रैकिंग जैसी विभिन्न रूपों का उपयोग करके एक रीयल-टाइम इंटरफ़ेस वेबसाइट है। ऐसा डैशबोर्ड और पोर्टल होना चाहिए जहां सिविल सोसाइटी भी प्रभावी रूप से भाग ले सके। इन डैशबोर्ड का डेटा वीएनआर रिपोर्ट तैयार करने में मददगार होगा।

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना - कई विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी आवश्यक है लेकिन प्राथमिकता पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सर्व शिक्षा सुनिश्चित करना

[37] https://www.u4.no/publications/are-blockchain-technologies-efficient-in-combatting-corruption

[38] https://ssir.org/articles/entry/will_blockchain_disrupt_government_corruption

[39] https://qz.com/india/1325423/indias-andhra-state-is-using-blockchain-to-build-capital-amaravati/

[40] Kahn, Theodore;Baron, Alejandro;Vieyra, Juan Cruz, Digital Technologies for Transparency in Public Investment: New Tools to Empower Citizens and Governments, IDB, 2018

[41] https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/319308/6-Not-without-us-civil-society-role-implementing-SDGs.pdf

[42] https://www.data4sdgs.org/resources/2030watch-civil-society-monitoring-sdgs-country-level-0

है। स्वास्थ्य के लिए, डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों का विकास एक शक्तिशाली प्रवर्तक है जिसका उपयोग सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं पर एनसीडी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन में सिविल सोसाइटी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है।[43] ये सरकार की चिकित्सा योजनाओं के तहत टीके और दवाएं देने और कमजोर आबादी के पंजीकरण के लिए विशिष्ट स्वयं सेवी संस्थानों के चयन के माध्यम से किया जा सकता हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, डिजिटल एप्लिकेशन का उपयोग करके छात्रों के नामांकन में स्वयं सेवी संस्थानों का उपयोग किया जा सकता है और उन लोगों के लिए शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है जो स्कूलों जाने में सक्षम नहीं हैं।

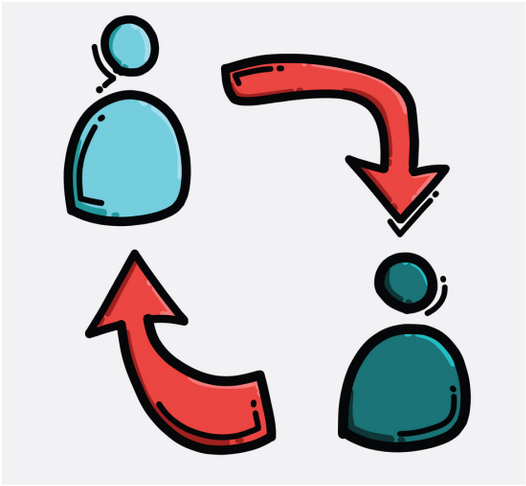

पीपल टू पीपल एक्सचेंज को बढ़ाना

सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया ब्रिक्स देशों के पारस्परिक लाभ के लिए पीपल टू पीपल एक्सचेंज के दायरे और बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से आग्रह करता है। विकास के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिविल सोसाइटी के आदान-प्रदान और क्रॉस-लर्निंग को बढ़ाया जा सकता है।

ब्रिक्स की विकास परियोजनाओं में भारतीय सिविल सोसाइटी संगठनों को शामिल करना- विकास सहयोग सिद्धांतों के अनुरूप, ब्रिक्स देशों में विकास परियोजनाओं में सिविल सोसाइटी को शामिल किया जाना चाहिए और देशों की परियोजना में सिविल सोसाइटी संगठनों को जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कई राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और अन्य स्वयं सेवी संस्थान विकास सहयोग पर सार्वजनिक वार्तालाप को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर युवाओं और समाज के अन्य वर्गों को सहयोग और विकास के मुद्दों पर शिक्षित करते हैं। एनजीओ और सीएसओ भी अधिक और बेहतर विकास सहयोग का पक्ष समर्थन करते हैं, और सरकारों को उनकी विकास प्रतिबद्धताओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अधिकांश ओईसीडी देशों और उनकी विकास सहायता समिति की सहकर्मी समीक्षा जन जागरूकता बढ़ाने और विकास के लिए राजनीतिक सहयोग सुरक्षित करने के लिए सिविल सोसाइटी के साथ सक्रिय जुड़ाव की सलाह देते हैं।[44]

विकास सहयोग में स्वयं सेवी संस्थानों की भागीदारी के लाभ

कई भारतीय स्वयं सेवी संस्थान जिनकी अपनी कार्यशैली है, ने अन्य विकासशील देशों को एकजुटता और सहयोग प्रदान किया है ! दीर्घकालीन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान, प्रौद्योगिकी और कौशल सहायता प्रदान की है; स्थानीय समुदाय, स्वयं सेवी संस्थान और उप-राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सरकारें उनके भागीदारों में शामिल हैं। गरीबी, बहिष्करण और असमानता के विषयो के तहत विकसित कार्यप्रणाली, स्थानीय रूपांतरण अन्य विकासशील देशों में सम्बंधित साबित हुआ है। कुछ मामलों को छोड़कर, इन प्रयासों ने मुख्य रूप से विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) देशों, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के द्विपक्षीय दानकर्ताओं और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियो से सहयोग और वित्तपोषण प्राप्त किया है।[45]

- शिक्षा क्षेत्र में आदान-प्रदान - नीति निर्माताओं के सुविधाजनक तर्क से भारत और ब्रिक्स देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में आदान-प्रदान की सुविधा के माध्यम से सहयोग

[43] https://ncdalliance.org/news-events/news/realising-the-promise-of-digital-health-for-ncds-and-uhc-what-is-the-opportunity-for-civil-society

[44] How DAC Members Work With Civil Society Organisations: An Overview, 2011

[45] Bandyopadhyay,KaustuvKanti, CSOs in Indian Development Cooperation: Towards an Enabling Environment, PRIA, 2017

प्राप्त किया जा सकता है।[46] हालांकि, ब्रिक्स देशों में विकास अध्ययन और सामाजिक-आर्थिक सहयोग में शिक्षा की सुविधा फायदेमंद हो सकती है, जो ब्रिक्स देशो की चुनौतियों के बारे में युवा पीढ़ी को सूचित करती है। सिविल सोसाइटी के सुझाव के रूप में - हमें लगता है कि एक आदर्श शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत दूसरे देशों के छात्रों को सीएसओ आमंत्रण और इन्क्यूबेशन पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए जिससे उन्हें जमीनी स्तर से विकास के मुद्दों से परिचित कराने में मदद मिलेगी। अकादमिक और समाज सेवी दोनों ही क्षेत्रों में विकास चुनौतियों पर ज्ञान आयोजन और प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसे उपाय पेश करते हैं जिनका उपयोग वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण के लिए किया जा सकता है।[47]

- युवा कार्यक्रमों के आदान-प्रदान में सिविल सोसाइटी के साथ साझेदारी - ब्रिक्स मंचों ने युवा से युवा को जोड़ने पर जोर दिया है। सिविल सोसाइटी के सुझाव के रूप में, हमें लगता है कि परस्पर सांस्कृतिक शिक्षा और देश भ्रमण को विकसित करना महत्वपूर्ण है।[48] सिविल सोसाइटी समूहों द्वारा युवा चैरिटी टूर्नामेंट की सुविधा से विभिन्न स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों पर जागरूकता बड़ाई जा सकती है। कई सिविल सोसाइटी संगठन खेलों को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं और भारत में विभिन्न स्थानों पर टूर्नामेंटों के आयोजन में भागीदार बनना चाहते हैं।

राष्ट्रीय विकास के लिए सुझाव[4950]

- भारतीय सिविल सोसाइटी के रूप में, हम भारत सरकार से राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थागत मंच के माध्यम से उचित वित्त पोषण और समाज सेवा क्षेत्र, निजी क्षेत्र और शिक्षा के साथ साझेदारी में दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों को लागू करने का अनुरोध करते हैं।
- हम भारत सरकार से विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण में वृद्धि करने का आग्रह करते हैं जो लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण हैं, सकल घरेलू उत्पाद को स्वास्थ्य अनुपात में बढ़ाकर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें। यह कोविड-19 वृद्धि के विषय में है, जिसके लिए हम सरकार से सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में अंतराल का मानचित्र विश्लेषण करने का अनुरोध करते हैं।
- 12 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त, समावेशी और सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करे जिससे शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हो।
- सामाजिक विकास योजनाओं को फंड देने के लिए प्रगतिशील कर प्रणाली को बढ़ाना जो एसडीजी के कई लक्ष्यों और संकेतकों को प्राप्त करने में मदद करे और वित्तीय न्याय के लिए रास्ता बनाये।
- विभिन्न राष्ट्रीय योजनाए और कार्यक्रम लिंग आधारित हो जिससे उन लाखों महिलाओं को मदद मिलेगी जो लैंगिक भेदभाव के बोझ तले दबी हुई हैं

[46] Varghese, N.V BRICS and International Collaborations in Higher Education in India, 2015, https://www.researchgate.net/publication/281806512_BRICS_and_International_Collaborations_in_Higher_Education_in_India

[47] Tandon, Rajesh, Civil engagement in Higher Education and its role in human and social development, 2008/01/01

[48] Tom Dwyer (University of Campinas, Brazil) ,Mikhail K Gorshkov (Russian Academy of Sciences, Russia),Ishwar Modi (University of Rajasthan, India),Chunling Li (Chinese Academy of Social Sciences, China) and Mokong Simon Mapadimeng (University of Limpopo, South Africa), Handbook of the Sociology of Youth in BRICS Countries

[49] INDIA & G20 Analyzing Development Dimensions of Policy Priorities, VANI, https://www.vaniindia.org/admin-latest/images/India%20and%20G20%20Analyzing%20Development%20Policy%20Priorities.pdf

[50] https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2015/08/Policy-Recommendations-for-the-Civil-BRICS-BRICS-Summit-2016-ECSN-BRICSAM-Oxfam-India-WNTA-PBI.pdf

- लक्षित पहलों के माध्यम से महिलाओं और दलितों, आदिवासियों जैसे कमजोर समुदायों के लिए आजीविका को बढ़ावा देना

- राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सिविल सोसाइटी के सहयोग से आजीविका, दवाओं और हमारी हस्तकला (सांस्कृतिक विरासत) की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देना

- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित संरचना और अर्थव्यवस्था के लिए पहल को बढ़ावा देना

- व्यापार और निवेश नीतियां बनाते समय लोगों के प्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों को शामिल करना

- सामुदायिक समूहों, वनवासियों, सिविल सोसाइटी संगठनों आदि के साथ बड़े पैमाने पर संरचना परियोजनाओं का संचालन करते समय एफपीआईसी से परामर्श करना।

- नियामक व्यवस्था में छूट देकर सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करना

HEINRICH BÖLL STIFTUNG
INDIA

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

www.vaniindia.org

About VANI

As a platform, it promotes voluntarism and creates space for voluntary action. As a network, it attempts to bring about a convergence of common sectoral issues and concerns for building a truly National agenda of voluntary action in the country. It also facilitates linkages of various efforts and initiatives of the voluntary sector.